वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त): (क) वरौनी में नैपया का मूल्य 121 रुपये प्रति टन हैं और रेल भाइा, उत्पादन गुल्क और केन्द्रीय बिकी कर आदि के कारण राउरकेला में इसका मूल्य लगभग 214 रुपये प्रति टन हो जाता है। अतः दूरी के कारण उत्पादन लागत में बृद्धि हो जाती है। फिर भी 18 मई, 1969 से जब एक विस्फोट के कारण नैपया रिफार्मिंग यूनिट के रिफार्मर्र फर्नेंस को श्रति पहुंची थी, उबंरक कारखाने में नैपया का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः इस समय इस करण से कोई अन्तर नहीं पड रहा है।

राउरकेला के उर्वरक कारखाने में अन्त-किया पदार्थ के रूप में अमोनियम नाइट्रेट बनता है जिसे ठोस बनने से बचाने का ध्यान रखा जाता है तथा कैनिशयम अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए इसमें पिसा हुआ चुना पत्थर मिलाया जाता है।

(ख) राउरकेला में नैपथा के अधिक मूल्य पर विचार किया गया है और इस अधिक मूल्य के बावजूद भी आणा है कि नैपथा रिफार्मिंग यूनिट की मरम्मत हो जाने के बाद जब पूरी क्षमता पर उत्पादन होने लगेगा तब राउरकेला उबंरक कारखाना लाभ अजित करेगा।

इस्पात कारखानों में हाईड्रोजन गैस के स्थान पर एल० एस० जी० डी० तेल का प्रयोग

4964. श्री महाराज सिंह भारती: क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात कारखानों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही हाईड्रोजन गैस के स्थान पर एल० जी० डी० तेल का प्रयोग करने तथा उर्वरक तैयार करने के लिये इस गैस का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय कोक ओवनगैन से है जिसमें हाइड्रोजन होती है। राउरकेला में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोक ओवन गैस की कमी से इस्पात कारखाने या उर्वरक कारखाने के सामान्य परिचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, स्लैब री-हीर्टिंग फरनेसों में कोक ओवन गैस के प्रयोग के. बजाय फरनेस आयल प्रयोग करने की मुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। भिलाई और दुर्गापुर कारखानों के सभी एककों को ईंधन की लगातार मण्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी फरनेम आयल का प्रयोग करने का विचार है।

राउरकेला में कोक ओवन गैस पर आधारित एक उबंरक कारखाना है जहां से हाईड्रोजन प्राप्त की जाती हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेंड के दूसरे दो कारखानों के लिए ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

घटिया किस्म के सीमेंट और सीमेंट की कम
मात्रा वाली सीमेंट की बोरियों की बिकी

4965. श्री प० ला० बारूपाल: क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विभिन्न सीमेंट कारखानों की सीमेंट की ऐसी वोरियां अभि-कर्ताओं द्वारा बेची जा रही हैं, जिनमें सीमेंट अपेक्षित मात्रा में नहीं होता;
- (ख) क्या यह भी सच है कि आजकल कारखानों में जो सीमेंट बनाया जा रहा है, वह पहले वाले सीमेंट की तुलना में कमजोर है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि राजस्वान नहर के निर्माण में इसी घटिया किस्म की सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है और श्री-

गंगानगर जिले में भी इसका वितरण किया जा रहा हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमव): (क) सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

- (ख) और (ग). जी नहीं, देश में उत्पा-दित सीमेंट भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनरूप हैं।
 - (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

SUPPLY OF STEEL BY TATA IRON AND STEEL COMPANY TO U.S.A.

4966. SHRI S. R. DAMANI; Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that the U.S. Government has placed an order with the Tata Iron and Steel Company for the supply of 17,500 tonnes of steel costing more than one million dollars;
- (b) if so, when this order was procured and the items to be supplied; and
- (c) whether the prices offered are on par, or higher or lower than the export prices for similar items of the Hindustan Steel Limited?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT); (a) and (b), Tata Iron and Steel Company Limited are understood to have booked some orders for supply of about 27,000 tonnes of steel at a price exceeding \$1 million from private parties in the U.S.A. No orders have been placed by the U.S. Government.

(c) There are only two common items for which orders have been booked both by Tata Iron & Steel Company and Hindustan Steel Limited. In both these cases the prices booked by Tata Iron & Steel Company were slightly lower than those of Hindustan steel Limited, but since the orders were booked at different points of time no conclusions can be drawn therefrom.

EXPENDITURE ON KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES

4967. SHRI S. K. SAMBANDHAN: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVE-LOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

- (a) the amount spent in the year 1968-69 on the Khadi and Village Industries;
- (b) the basis or criterion on which the above amount was spent; and
- (c) whether Government propose to revise the same on the basis of the number of people depending on the industry?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) The Khadi and Village Industries Commission has informed that the expenditure incurred during 1968-69 for the development of Khadi and Village Industries from the funds sanctioned by Government and those available with the Commission is as under:

(Rs. crores)

		Khadi	V.I.	Total
Grant		8 - 98	1 ·56	10 .54
Loan		3 -98	6 -84	10.82
Total	:	12.96	8 -40	21 ·36

- (b) The basis on which the amount is spent is governed by the various patterns of assistance approved by the Commission and the Government from time to time. The expenditure was mainly on financial assistance for working capital and capital investment loans including share capital loans, grant for training and research and for procuring improved tools and equipment and subsidy for reducing the price differential or for increasing sales.
- (c) Recently the Khadi and Village Industries Committee under the Chairmanship of Shri Ashok Mehta had, among other things, gone into the questions connected with employment in the traditional industry sector. The matter is at present being examined by Government in consultation with the State Governments.